



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 7, 2004/आश्विन 15, 1926

No. 164]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2004/ASVINA 15, 1926

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 4 अक्टूबर, 2004

सं. टीएमपी/66/2003-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, हालिदया में कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों के किराए की अनुसूची में संशोधन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण को, संलग्न ओदशानुसार, बंद करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/66/2003-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

## आदेश

(सितम्बर 2004 के 30वें दिन पारित)

यह प्रकरण हालिदया में केओपीटी की भूमि और भवनों के किराए की अनुसूची में संशोधन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। केओपीटी के प्रस्ताव को प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और उस पर, निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई थी।

2. तत्पश्चात, केओपीटी ने दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अपने पत्र द्वारा, हालिदया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के लिए वर्तमान किराया अनुसूची में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

3. इसी समय, भारत सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय में, मार्च 2004 में, (मुंबई और कोलकाता के अलावा) महापत्तनों के लिए भूमि

नीति की घोषणा की। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई, 2004 के अपने पत्र द्वारा स्पष्ट किया है कि केओपीटी और एमबीपीटी के लिए भूमि नीति विचाराधीन है और हालिदया स्थित केओपीटी की भूमि को, केओपीटी की भूमि नीति द्वारा, जब कभी उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा, समाहित कर लिया जाएगा। केओपीटी को सलाह दी गई थी कि वह संदर्भित प्रस्ताव की, केओपीटी के लिए लागू होने वाली, महापत्तनों के लिए लागू होने वाली भूमिनीति के प्रकाश में समीक्षा करे, और इस प्राधिकरण के समक्ष नया प्रस्ताव प्रस्तुत करे। केओपीटी, पोत परिवहन मंत्रालय से भूमि नीति मिलने पर संदर्भित प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया है।

4. जैसाकि, केओपीटी भूमि पर लागू होने वाली नई नीति सरकार द्वारा शीघ्र घोषित की जाने वाली है, इस प्रकार के नीति निर्णयों के अनुरूप किराया-अनुसूची को निर्धारित करना युक्तिसंगत होगा। केओपीटी भी, अपने प्रस्ताव को तदनुसार संशोधित करने के लिए सहमत हो गया है। ऐसा होते हुए संदर्भित प्रकरण बंद होता है। नई भूमि नीति घोषित होने के बाद केओपीटी को, वर्तमान दरों की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव फाइल करना चाहिए। केओपीटी को, सरकार द्वारा नई नीति घोषित करने की तिथि से, इस प्रकार का प्रस्ताव फाइल करने हेतु 60 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

5. केओपीटी के प्रस्ताव में, कुछ मामलों में, वर्तमान दरों में कमी भी शामिल है। प्रकरण को बंद करने का निर्णय इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी दरों को उच्चतम दरें घोषित करने के लिए पहले से अपनाई गई सामान्य नीति की दृष्टि से, यदि वह ऐसा चाहे तो केओपीटी द्वारा ऐसी कम दरें लागू करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए।

6. तत्पश्चात, केओपीटी ने, सरकार द्वारा पहले से महापत्तनों के लिए (केओपीटी और एमबीपीटी के अलावा) घोषित भूमि नीति के आधार पर वर्तमान संशर्तताओं में से कुछ में संशोधन के लिए प्रस्ताव

किया है। सरकार द्वारा केओपीटी के लिए नई भूमि नीति घोषित करने के बाद दरों की समीक्षा करने के निर्णय के अनुरूप, संशर्तताओं में संशोधन भी, पत्तन द्वारा फाइल किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव पर आरम्भ की जाने वाली कार्रवाई के साथ किया जा सकता है।

अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन/III/IV/143/2004-असा. ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 4th October, 2004

**No. TAMP/66/2003-KOPT.**— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports closes the case relating to the proposal received from the Kolkata Port Trust for revision of Schedule of Rent for Land and Buildings of Kolkata Port Trust at Haldia as in the order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/66/2003-KOPT

The Kolkata Port Trust

Applicant

### ORDER

(Passed on this 30th day of September, 2004)

This case relates to a proposal from the Kolkata Port Trust (KOPT) for revision of Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Haldia. The KOPT proposal was registered as a tariff case and further processed following the consultative procedure prescribed.

2. Subsequently the KOPT *vide* its letter dated 11 August, 2004 proposed certain amendments to the existing Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT at Haldia.

3. In the meanwhile, the Government of India in the Ministry of Shipping announced Land Policy for Major

Ports (except Mumbai and Kolkata) in March 2004. The Ministry of Shipping (MOS) *vide* its letter dated 26 July, 2004 has further clarified that the Land Policy for KOPT and MBPT is under consideration and the lands of KOPT situated at Haldia will be covered by the Land Policy of KOPT whenever finalized. The KOPT was advised to review its proposal in reference in the light of the Land Policy for Major Ports applicable for KOPT and file a fresh proposal before this Authority. The KOPT has agreed to revise its proposal in reference on receipt of the Land Policy from MOS.

4. Since the new policy applicable to KOPT lands is to be announced by the Government soon, it will be appropriate to fix schedule of rents in line with such policy decisions. The KOPT has also agreed to revise its proposal accordingly. That being so, the case in reference is closed. After the new land policy is announced the KOPT should file its proposal for a review of the existing rates. The KOPT is granted 60 days' time from the date Government announces the new policy to file such a proposal.

5. The proposal of KOPT includes reduction in the existing rates in some cases. The decision to close the case should not come in the way of KOPT implementing such reduced rates, if it desires so, in view of the general policy decision already taken to declare all the rates fixed by this Authority as ceiling rates.

6. The KOPT has subsequently proposed amendments to some of the existing conditionalities based on the land policy for major ports (other than KOPT and MBPT) already announced by the Government. In line with the decision to take up review of rates after the new land policy for KOPT is announced by Government, the amendments to conditionalities can also be taken up for consideration in the proceeding to be initiated based on a revised proposal to be filed by the port.

A.L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/2004-Exty]